



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2481]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का. आ. 2829(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए “गुजरात विद्युत विनियामक आयोग” एक आयोग जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन हुआ है, को, होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, यथा:-

- सरकार से प्राप्त अनुदान और सहायता की रकम;
  - दर-निर्धारण में प्राप्त याचिका शुल्क एवं प्रक्रिया फीस के रूप में प्राप्त धनराशि;
  - लाइसेंस शुल्क एवं आवेदन शुल्क अथवा जुर्माने के रूप में प्राप्त धनराशि;
  - दस्तावेजों का शुल्क;
  - वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देरी के लिए प्राप्त शास्ति अथवा ब्याज; और
  - आर.टी.आई. का शुल्क।
2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि गुजरात विद्युत विनियामक आयोग:—
- किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
  - वित्तीय वर्ष में यह विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
  - यह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी एवं यह वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20 एवं 2020-21 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 84/2017/फा.सं.300196/8/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

**व्याख्यात्मक ज्ञापन.**—यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2017

**S. O. 2829(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Gujarat Electricity Regulatory Commission', a Commission constituted under the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amounts received in form of grants and aid from Government;
- (b) amount received in the form of petition fees or processing fee for determination of tariff;
- (c) amount received in the form of License fees; Application fees or in nature of fines;
- (d) interest earned on investment or deposit or Saving/Current Bank Accounts;
- (e) fees for documents;
- (f) penalty or interest for delayed payment of Annual License fees; and
- (g) fees for RTI.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat Electricity Regulatory Commission:—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2016-2017 and shall apply with respect to financial years 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021.

[Notification No. 84 /2017/F. No. 300196/8/2017-ITA-I]  
DEEPSHIKHA SHARMA, Director

**Explanatory Memorandum.**—It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.